अंक: ५ | अक्टूबर २०१५ – मार्च २०१६

आई. सी. डब्ल्यू. ए. समाचार पत्रक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्, सप्रू हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली

सप्रू हाउस, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम

नेपाल सरकार के प्रधानमंत्री माननीय श्री के पी शर्मा ओली द्वारा २१ सप्रू हाउस व्याख्यान

२२ फरवरी २०१६

विश्व मामलों की भारतीय परिषद् ने २२ फरवरी २०१६ को सप्रू हाउस में २१ सप्रू हाउस व्याख्यान आयोजित करवाया। यह व्याख्यान नेपाल के प्रधानमंत्री श्री के पी शर्मा ओली द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने उप प्रधानमंत्री कमल थापा के साथ शिरकत की तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने की। अपने स्वागतीय उद्बोधन में आई.सी.डब्ल्यू.ए. के महानिदेशक राजदूत नलिन सूरी ने कहा कि यह यात्रा भारत और नेपाल के मध्य वर्षों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाती है। श्रीमती सुषमा स्वराज ने अपने वक्तव्य में प्रशंसा करते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्ते सरकारों के संवाद के मोहताज नहीं है, अपितु ये लोगों के वृहद स्तर पर आपस में संपर्क के कारण स्व पोषित है। उन्होंने दोनों देशों के उन्नत होते रिश्तों और दोनों देशों द्वारा चुनौतियों में अपनाये गये रास्तों का पर भी बात की।

परिषद् की प्रमुख उपलब्धियाँ

- नेपाल सरकार के प्रधानमंत्री माननीय श्री के पी शर्मा ओली द्वारा २१ सप्रू हाउस व्याख्यान
- मैक्सिको की विदेश मंत्री महामहिम श्रीमती क्लोडिया रूईज – मैस्यू सेलीनेस द्वारा 22वां सप्रू हाउस व्याख्यान
- आईसीडब्ल्यूए–आईएफएएनएस (इंस्टिट्यूट ऑफ फोरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्यूरिटी) संवाद
- सप्रू हाउस में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमण्डल की सहभागिता में "भारत यूएस साझेदारी" पर गोलमेज का आयोजन
- नेपाल में भारत के राजदूत श्री रनजीत राय द्वारा वार्ता
- स्लोवानिया की संसद के स्पीकर महामहिम डॉ मिलान बग्रेल्ज द्वारा २०वाँ सप्रू हाउस व्याख्यान
- राजदूत समन्था पॉवर, अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि द्वारा व्याख्यान
- पूर्वान्ह - भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन -III अकादमिक सम्मेलन
- हिंदी में विदेश नीति जागरूकता कार्यक्रम

इस अवसर पर नेपाल के उपप्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री कमल थापा ने अपना विशिष्ट अभिभाषण प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि दोनों देशों की गहरी निकटता एवं सम्बन्धों ने सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना किया है तथा आगे भी ये सम्बन्ध मजबूत रहेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान संविधान सभी सार्वभौमिक लोकतान्त्रिक मूल्यों को समावेशित करता है। यद्यपि लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व के बारे में उन्होंने कहा कि नेपाल एक प्रगतिशील समाज है हालाँकि नेपाली समाज के कुछ वर्ग संविधान से प्रसन्न नहीं है। इन लोगों की मांगों को संविधान की रुपरेखा के तहत विभिन्न तंत्र एवं तरीकों से पूरा किया जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने अपने मुख्य अभिभाषण को दो भागों में प्रस्तुत किया: प्रथम, नेपाल का राजनितिक विकास; और द्वितीय, नेपाल का भारत के साथ सम्बन्ध। उन्होंने मोदी की यात्रा को 'एतिहासिक यात्रा' बताया जिसने नेपाल के लोगों के दिल और दिमाग से सभी शंकाओ को दूर किया है। उन्होंने भूकंप के दौरान भारत द्वारा की गयी सहायता की प्रशंसा की और कहा कि यह सहायता एक प्रकार से दोनों देशों के मध्य प्रेम और समझ को अभिव्यक्त करती है। उन्होंने नेपाल में पिछले दस सालों में हुए राजनीतिक परिवर्तन की बात कही जहाँ राजतंत्र से देश में संघीय लोकतान्त्रिक शासन की स्थापना हुई है। उन्होंने वर्तमान संविधान के निर्माण और इसको बनाने की विधियों के बारे में विस्तार से बतलाया।

भारत नेपाल सम्बन्धों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय रिश्ते काफी व्यापक, गहरे और बहु आयामी है तथा केवल औपचारिक दस्तावेज एवं संधियाँ ही इसका आधार नहीं है। विश्व में आज ऐसे बहुत कम राष्ट्र है जिनका इतिहास और भविष्य इतना सामीप्य है कि वे एक दुसरे से काफी अंतर्संबंधित है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि यदि उन्हें भारत और नेपाल के रिश्ते को परिभाषित करने के लिए कहा जाये तो इस सम्बन्ध के लिए एक शब्द है 'संप्रभु भातृत्व' ।

उन्होंने भारत तथा चीन के साथ नेपाल के सम्बन्धों का भी जिक्र किया। उन्होंने आगे कहा कि नेपाल दोनों में ही हो रहे आर्थिक विकास, विज्ञानं, तकनीकी, सूचना तकनीकी और व्यापार से लाभ लेना चाहता है। उन्होंने कहा कि नेपाल पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह भारत और चीन के खिलाफ विभिन्न प्रकार के कार्ड खेलता है। हालाँकि उन्होंने इसे निराधार बताया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन नेपाल के दो बड़े पडौसी मित्र है और नेपाल दोनों से अच्छे सम्बन्ध बनाना चाहता है और दोनों से ही लाभ लेना चाहता है।

भारत की संवेदनशीलता और सुरक्षा के संदर्भ में प्रधानमन्त्री ओली ने कहा कि नेपाल अपनी धरती पर भारत विरोधी किसी भी गतिविधि को संचालित नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत को ऐसे सुदृढ़ प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे कि वे अपनी भूमि को किसी अन्य शोषणकारी तत्वों द्वारा दुरूपयोग नहीं करने देंगे जो कि दोनों देशों के हितों को निर्णायक क्षति पहुंचाते हो। उन्होंने आर्थिक एवं उर्जा के क्षेत्रों में सहयोग की बात दोहरायी तथा कहा कि नेपाल जब अतिरिक्त उत्पादन करने लगेगा तब वे इसे पुनः भारत को लौटा देंगे. निष्कर्षतः उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के रिश्ते आगे की तरफ बढ़ने वाले तथा प्रगतिशील होने चाहिए तथा विकास एवं समृद्धता के लिए एक मजबूत नीव होनी चाहिए।

मैक्सिको की विदेश मंत्री महामहिम श्रीमती क्लोड़िया रूईज–मैस्यू सेलीनेस द्वारा २२ वां सप्रू हाउस व्याख्यान

११ मार्च २०१६

११ मार्च २०१६ को विश्व मामलों की भारतीय परिषद् ने "मैक्सिको का अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य भारत मैक्सिको संबंध विषय पर २२वां सप्रू हाउस व्याख्यान आयोजित किया गया। इसमें मैक्सिको की विदेश मंत्री महामहिम श्रीमती क्लोड़िया रूईज- मस्यू सेलिनेस ने विषय पर अपना अभिभाषण दिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आईसीडब्ल्यूए के महानिदेशक राजदूत नलिन सूरी ने की। 22वें सप्रू हाउस व्याख्यान पर चर्चा के दौरान मंत्री सेलीनेस ने भारत और मैक्सिको के मध्य उन्नत होते संबंधों पर बात की। उन्होंने मैक्सिको के साथ अमेरिका के संबंधों पर भी वृतान्त दिया, साथ ही लेटिन अमेरिका क्षेत्र की सामरिक स्थिति को भी दर्शाया। इसके अतिरिक्त विश्व में एक बडी अर्थव्यवस्था होने के नाते विश्व में भू-सामरिक तथा एक आर्थिक अभिकर्ता के रूप में मैक्सिको की बढती हुई भूमिका के बारे में बताया। महत्वपूर्ण संरचनात्मक समायेजन तथा आर्थिक सुधारों से गुजरते हुए मैक्सिको ने वैश्विक आर्थिक उन्नति तथा स्थिरता पर एक अमिट प्रभाव डाला है। उन्होंने बताया कि कैसे मैक्सिको भारत के प्रवासियों के अनुभव से सीख सकता है। बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य में यह नये आर्थिक प्रारूपों और व्यवस्थाओं को जन्म दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कैसे मैक्सिको वैश्विक सरकार, जलवायु परिवर्तन, सम्पोषित विकास के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कदम उठाने में सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहा है, साथ ही साथ इसने संयुक्त राष्ट्र में भी गतिशील भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि "मेक इन इंडिया" का भारतीय विजन तथा "मूविंग मैक्सिको" के मैक्सिकन विजन से दोनों अर्थव्यवस्थाएं पारस्परिक उत्पादों द्वारा कैसे लाभ प्राप्त कर सकती है। उन्होंने कहा "मैक्सिको के पास हमारे साझे भविष्य के लिए स्पष्ट विजन है। नवीनीकृत तथा मजबूत रिश्तों द्वारा, दोनों देशों को विभिन्न अवसरों का भरपूर लाभ लेना चाहिए।

भारत के विश्व भर में गतिशील क्षेत्रों में जाने हेतु मैक्सिको एक प्राकृतिक सेतु है. हमरा मुक्त व्यापार समझौता तथा सामरिक सहयोग का तंत्र उत्तरी अमेरिका तथा लेटिन अमेरिका में जाने का प्रवेश द्वार मुहैया करवाता है।

सप्रू हाउस में अमेरिका के अतिथि कांग्रेसनल प्रतिनिधिमण्डल की सहभागिता में "भारत यूएस साझेदारी" पर गोलमेज का आयोजन

१८ जनवरी २०१६

आईसीडब्ल्यूए के महानिदेशक, राजदूत नलिन सूरी ने अमेरिका से आये कांग्रेस के प्रतिनिधिमण्डल का स्वागत किया। राजदूत सूरी ने कहा कि भारत-अमेरिका संबंधों में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तन आये हैं।

उन्होंने यह इंगित किया कि इस परिवर्तन दोनों देशों को राजनैतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने आगे कहा कि कैसे दो विशाल और पुराने लोकतंत्र एक साथ आये हैं, लेकिन आपसी संबंधों में लोकतंत्र के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में अमेरिकी कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत को उच्च तकनीकी और बाजारों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुलभता की आवश्यकता है। उन्होंने आगे इंगित किया कि भिन्नताएं होना प्राकृतिक है और दोनों देशों को उन पर काबू पाने इन्हें तथा कम करने की जरुरत है। इसमें विश्वास निर्माण की सख्त आवश्यकता है और पुनः इसमें अमेरिकी कांग्रेस को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

अतिथि प्रतिनिधिमण्डल में बिली लोन्ग (आर.मिसूरी) ऊर्जा व्यापार और वाणिज्य सदन समिति के सदस्य हैं, डर्क किल्मर (डी वाशिंगटन) वित्तीय सेवाओं की सदन समिति तथा सदन प्रशासनिक के सदस्य है, कांग्रेस ब्रेन्डन बोयले (डी पेन्नसुलवानिया) विदेशी मामलों की सदन समिति के सदस्य हैं तथा भारत और भारतीय अमेरिकी के काकस के सदस्य हैं, और अमी बेरा (डी कैलीफोर्निया) भारत और भारतीय अमेरिकी काकस के सदस्य तथा उपाध्यक्ष हैं।

इस पर चर्चा की गयी कि विगत कुछ वर्षों में अमेरिका और भारत के रिश्ते किस प्रकार उभरे हैं। किस प्रकार से अमेरिकी प्रशासन का ध्यान/केंद्र भारत रहा है और कैसे यह अमेरिका की एशिया नीति की धुरी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अमेरिका में प्रवासी भारतीय की बढ़ती परिपक्वता ने परिवर्तनकारी भूमिका अदा की है। इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर इस गोलमेज में चर्चा हुई।

.

महामहिम श्री रंजीत राय, नेपाल में भारत के राजदूत, द्वारा "द करन्ट सिचुएशन इन नेपाल" विषय पर वार्ता, राजदूत नलिन सूरी, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए द्वारा अध्यक्षता
११ जनवरी २०१६

११ जनवरी, २०१६ को नेपाल में भारत के राजदूत रनजीत राय द्वारा नेपाल की वर्तमान परिस्थिति के बारे में विश्व मामलों की भारतीय परिषद्, नई दिल्ली में अपने विचार व्यक्त किये। राजदूत राय का यह अभिभाषण नेपाल के चल रही वर्तमान समस्याओं से संबंधित मुख्य बातों को व्यापक रूप से सामने रखने का प्रयास था. उन्होंने वर्तमान समस्या पर अपने विचार साझे किये तथा आन्दोलनकारियों की दुविधा तथा भारत के दृष्टिकोण पर भी अपनी राय प्रस्तुत की। इस वार्ता की अध्यक्षता राजदूत नलिन सूरी, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए ने की तथा इसमें विद्दवानजन, कूटनीतिज्ञ, अकादमिक तथा पत्रकार भी शामिल हुए।

भारत की नेपाल नीति पर बात करते हुए राजदूत राय ने कहा कि भारत चाहता है कि नेपाल में शांति और स्थिरता की स्थापना हो। उन्होंने माना कि मुख्य राजनीतिक दलों तथा मधेशी आन्दोलनकारियों के बीच पनपे मतान्तर का जल्द ही संवादों के द्वारा निराकरण होगा।

स्लोवानिया की संसद के स्पीकर महामहिम डॉ मिलान बग्रेल्ज द्वारा "स्लोवानियज डिकेड इन द यूरोपियन यूनियन – ए लुक बैक एण्ड आपरच्यूनिटीज फॉर द फ्यूचर" विषय पर २० वां सप्रू हाउस व्याख्यान, राजदूत दिनकर खुल्लर द्वारा अध्यक्षता

२६ नवम्बर २०१५

२६ नवम्बर, २०१५ को २०वें सप्रू हाउस व्याख्यान पर स्लोवानिया की संसद के स्पीकर डॉ मिलान ब्रगेल्ज द्वारा "स्लोवानियाज डीकेड इन द यूरोपियन यूनियन – ए लुक बैक एण्ड आपरच्यूनिटिज फॉर द फ्यूचर" विषय पर अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजदूत दिनकर खुल्लर ने की। अपने स्वागतीय अभिभाषण में आईसीडब्ल्यूए के उप महानिदेशक श्री अजनीश कुमार ने यूरोपियन यूनियन की राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताया, जिसमें आर्थिक मंदी, आव्रजन इत्यादि उभरती हुई समस्याएं भी शामिल है। अपनी टिप्पणी में राजदूत खुल्लर ने स्लोवानिया के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्तों के बारे में बताया जब यह देश युगोस्लाविया का हिस्सा था। यूगोस्लानिया के विखण्डन के बाद वर्ष २००४ में स्लोवानिया यूरोपिय यूनियन से जुड़ गया। वर्ष २००८ में यूरोपियन यूनियन की परिषद की आवर्ती अध्यक्षता का अवसर स्लोवानिया को मिला। राजदूत खुल्लर ने यूरोप में वर्तमान राजनीतिक तथा सुरक्षा समस्याओं और विशेष रूप से सुरक्षा मुद्दे, आर्थिक संकट तथा प्रवप्रन संकट पर बातचीत की।

अपने उद्बोदन में, डॉ मिलान बर्गेज ने यूरोपियन यूनियन के स्लोवानिया के दृष्टिकोण के साथ साथ यूरोपियन यूनियन तथा स्लोवानियाकी वर्तमान चुनौतियों पर चर्चा की। यूरोपियन यूनियन के विकास और इसकी प्रकृति का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन परा-राष्ट्रीय संस्था या संगठन है। डॉ बर्गेल्ज ने इंगित किया कि यूरोपियन एकीकरण की नींव वस्तुओं, मुद्रा, सेवाओं और लोगों के मुक्त प्रवाह पर आधारित थी।

स्लोवानिया यूरोपियन यूनियन के बाजार पर अधिक आश्रित था तथा परिवर्तित विश्व में यह दयनीय था। यधपि उन्होंने तर्क दिया कि छोटे सदस्य राष्ट्र यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति और साझी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्लोवानिया ने विकास के सतत् तरीकों को अपनाया तथा हरित अर्थव्यवस्था को प्रोन्नत किया। डॉ ब्रगेल्ज ने इंगित किया कि ज्ञान, शोध और विकास काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा देश शोध एवं विकास में काफी व्यय कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोपियवाद का स्लावानिया पर काफी कम प्रभाव है। यूरापिय केन्द्रित दल वर्ष २०१४ में यूरोपीय संसद के चुनावों में जीत गये। यहां आवश्यकता इस बात की है कि यूरोपियन यूनियनके बारे में समझ को और बढाया जाये। भारत यूरोपियन यूनियन के संबंध में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जर्मनी फ्रांस और यूके की यात्रा की, और छोटे यूरोपियन देशों के नेता भारत की यात्रा कर रहे हैं उन्होंने कहा की यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल के बारे में स्लोवानिया के नागरिक नकारात्मक सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि स्लोविया के लोग गुट निरपेक्ष आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। यूरोपियन यूनियन शरणार्थियों की समस्या को सुलझाने हेतु प्रयासरत है। उन्होंने रेखांकित किया कि यूरोप में शरणार्थियों की समस्या को सुलझाने में तुर्की की महत्वपर्ण भूमिका होगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यूरोपियन यूनियन के छोटे देशों को प्रवासियों को समायोजित करने में समस्यों उत्पन्न होगी। अर्थव्यवस्था के संकट पर बोलते हुए उन्होंने वर्तमान यूरोप के आर्थित विकास की प्रवृत्तियों पर चर्चाकी एवं कहा कि यूनान संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है।

राजदूत समन्था पॉवर, अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि द्वारा व्याख्यान

राजदूत समन्था पॉवर, अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि द्वारा "टुवार्ड मोर इफेक्टिव पीस कीपिंग इन द ट्वंटी फर्स्ट सेन्चुरी" पर २० नवम्बर २०१५ को सप्रू हाउस, नई दिल्ली में विशेष व्याख्यान.

२१वीं शताब्दी में प्रभावशाली शान्तिरक्षण पर व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा की भारत एक सक्षम नेतृत्व के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत ने सर्वप्रथम कोरिया में संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में अपने सैन्य अस्पतालों और क्षेत्रीय एम्बूलेंसो द्वारा सहायता दी तथा उसके बाद भारत ने वर्ष १९५६ में संयुक्त राष्ट्र की शान्ति रक्षा के अन्तर्गत मिश्र के स्वेज में अपनी शांति रक्षा सेना को नियुक्त किया। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के अभियानों से पहले शान्ति रक्षक सेनायें काफी विकसित हो चुकी थी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र "शान्ति सेनायें विभिन्न परिस्थितियों मे नियुक्त की जा चुकी थी, जहां उग्रवादी समूह और लडाकों के साथ वे निरन्तर संघर्षरत थी, काफी बार उन्होंने नागरिकों पर भी हमला किया। और इसके अलावा उन्होंने शान्ति रक्षक सेनाओं पर भी हमला किया. आज की तारीख में सक्रिय संघर्षो के क्षेत्रों में दो तिहाई शान्ति सेना सक्रिय है जो कि अभी तक प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक है। आगे, शांति रक्षकों से नई जिम्मेदारियाँ लेने के लिए कहा गया जो कि पहले के शांति रक्षकों से ज्यादा थी। पहले के कार्मिकों के लिए अपने नये उत्तराधिकारी के आदेशों/नियमों को पहचानना मुश्किल था, जिसमे शामिल थे- सैन्य समूह को निरस्त्रीकरण करना, मानवीय सहायता को सुरक्षित रूप से मुहैया कराना, युद्ध अपराध तथा अत्याचार के अपराधियों को जवाबदेह करना तथा नागरिकों को उन अपराधों से बचाना। इस अंतराल में, संकटों की संख्या ज्यादा बढ़ने से शांति रक्षकों की मांग भी बढ़ने लगी. कार्मिकों की थोड़ी सी संख्या १५ साल पहले २०००० बढ़ी, ५०००० की संख्या १० साल पहले बढ़ी तथा आज यह १००,००० हो गयी है। और इसमें वो २०,००० शांति रक्षक शामिल नहीं है जो सोमालिया में अफ्रीकन यूनियन के तहत सेवाएं दे रहे है। राजदूत पॉवर ने वर्णित किया कि विकट समय में शांति रक्षकों की भूमिका भारत और अन्य परम्परागत योगदान कर्ताओं के लिए बदल गयी है, जो कि अभी सैनिक योगदानकर्ताओं के रूप में एक बड़ा भाग साझा करते है।

ऐसे वातावरण में जहाँ मेजबान सरकार कमजोर हो वहाँ कार्मिकों का सहयोग किफायती तौर पर ही हो पाता है, ऐसे में कभी कभी दूसरा पक्ष हथियार नहीं डालता है तब ऐसी परिस्थिति में शांति रक्षकों के लिए खतरा बढ़ जाता है। ऐसे वातावरणों में, भारत के लम्बे समय तक रही प्रतिबद्धता 'मानवीयता के व्यापक कारण' के साथ भारत के परम्परागत अहस्तक्षेप की नीति तनाव को बढाती है। उन्होंने वर्तमान अमेरिकी नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना की सशक्त भूमिका की प्रतिबद्धता को दोहराया और यह भी बताया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोन्नत करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कदम उठाये। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सितम्बर २०१५ की घोषणा की तारीफ़ की, जहाँ कहा गया कि इन सब योगदानों के अतिरिक्त भारत अस्पताल, इंजीनियरिंग कम्पनी और एक कम्पनी जो कि संचार में मदद करेगी आदि को मुहैया करेगा। उन्होंने अंततः कहा कि यहाँ कार्मिकों के लिए चिकित्सा सहायता को उन्नत करने की त्वरित आवश्यकता है, तथा आपातकालीन सेवाओं के लिए उच्च मापदंडों युक्त चिकित्सा सेवाएँ चाहिए। कार्मिकों की सुरक्षा में निवेश की अधिक आवश्यकता है, जिसमे यह सुनिश्चित हो कि गैर अस्पताल के वातावरण में उनके पास आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षण हो। यहाँ शांति रक्षकों पर हमला करने वाले अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का अच्छा प्रबंध हो।

'इंडिया-अफ्रीका पार्टनरशिप: स्केल एंड स्कोप ऑफ कम्प्रेहेंसिव पार्टनरशिप' विषय पर पूर्वान्ह तीसरे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आयोजन १५ -१६ अक्टूबर

विश्व मामलों की भारतीय परिषद ने १५ -१६ अक्टूबर को सप्रू हाउस, नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सहयोग से पूर्व -तीसरे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आयोजन 'इंडिया-अफ्रीका पार्टनरशिप: स्केल एंड स्कोप ऑफ कम्प्रेहेंसिव पार्टनरशिप' विषय पर किया। मिस्र, इथोपिया, सुदान, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, मोरिशस, घाना तथा नाइजीरिया से आये शोधार्थियों और विशेषज्ञों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में भारत से विभिन्न वर्गों के अकादमिक, विशेषज्ञ, थिंक टैंक, विश्लेषक, व्यापारिक समूह, मीडिया तथा नीति निर्माताओं ने भी भाग लिया। दो दिवसीय सम्मेलन में परिचर्चा की संरचना ६ उपविषयों में विभक्त थी- राजनीतिक सहयोग, प्रोन्नत आर्थिक सम्बन्ध, शांति और सुरक्षा की चुनौतियाँ, विकास सहयोग, लोगों से लोगों का सम्पर्क तथा बहुपक्षीय जुड़ाव। आरंभिक सत्र में आई.सी.डब्ल्यू.ए. के महानिदेशक राजदूत नलिन सूरी तथा श्री नवतेज सरन, विदेश मंत्रालय उपस्थित थे। इस सत्र में विशेष संबोधन महामहिम श्रीमती जेनेट ज़ेविदे, डीन ऑफ द अफ्रीकन डिप्लोमेट्स कोर्प्स एंड एम्बेसेडर ऑफ इथोपिया द्वारा दिया गया। इस सम्मेलन में शामिल होने वाले अन्य व्यक्ति थे- डॉ सोलोमन देरसो, कमिश्नर इन द अफ्रीकन यूनियन कमीशन, इथोपिया, डॉ एलेक्स म्वाम्बा, लेक्चरर, यूनिवर्सिटी ऑफ जाम्बिया, एम्बेसेडर दिनकर खुल्लर एवं अन्य प्रतिष्ठित अकादमिक, शोधार्थी एवं नीति निर्माता। भारत-अफ्रीका सम्बन्ध तीन सी (c) पर आधारित है- कनेक्टिविटी, कोम्प्लिमेंटेरिटी तथा कोपरेशन. कनेक्टिविटी मुख्यतः लोगों से लोगों के संपर्क को जोड़ता है तथा कनेक्टिविटी की यह उपलब्धता सहयोग को बढाती है। सम्मेलन से यह आशा है कि ऊपर वर्णित रास्ते भारत और अफ्रीका के देशों को नजदीक लायेंगे।

.

दिल्ली से बाहर आयोजित कार्यक्रम

हिंदी में विदेश नीति जागरूकता कार्यक्रम, मथुरा: १-२ फरवरी २०१६

आर सी ए महिला महाविद्यालय, मथुरा में १-२ फरवरी २०१६ को दो दिवसीय सेमीनार आयोजित किया गया। आई.सी.डब्ल्यू.ए. के सौजन्य से आयोजित इस सेमिनार का विषय भारत की विदेश नीति और विशेष रूप से भारत की एक्ट ईस्ट पालिसी था। उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से शोधार्थियों और छात्रों ने इसमें भाग लिया। इस सेमीनार के मुख्य अतिथि प्रो एस डी मुनि ने मुख्य संबोधन दिया। सेमिनार में यह स्पष्ट हुआ कि एक्ट ईस्ट पालिसी १९९० के दशक की लुक ईस्ट नीति का विस्तार ही है, इसके अलावा इस नीति के भविष्य तथा एक्ट ईस्ट पालिसी का आसियान देशों प्रकार्यात्मकता और सफलता पर भी चर्चा की गयी। आई.सी.डब्ल्यू.ए. की तरफ से डॉ स्मिता तिवारी ने भाग लिया तथा एक शोध पत्र भी प्रस्तुत किया।

दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार- "इंडियाज एक्ट ईस्ट पालिसी: प्रोब्लेम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स इन नार्थ ईस्ट इंडिया", इम्फाल, मणिपुर, विमाभाप के सौजन्य से, २८-२९ जनवरी २०१६

इंदिरा गाँधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी. रीजनल केम्पस, मणिपुर ने दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार २८-२९ जनवरी २०१६ को आयोजित किया गया। इस सेमिनार में भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पालिसी के बारे में चर्चा हुई। इस सेमिनार में सम्पूर्ण क्षेत्र के प्रख्यात विद्वान एवं शोधार्थियों ने भाग लिया। आई.सी.डब्ल्यू.ए. की तरफ से डॉ ध्रुबज्योति भट्टाचार्य ने भाग लिया तथा एक शोध पत्र भी प्रस्तुतं किया।

तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार- "मल्टीलेटरल कोपरेशन: इमर्जिंग ग्लोबल सीनेरियो", तिरुपति, आई.सी.डब्ल्यू.ए. के सौजन्य से, २२-२४ फरवरी २०१६

तिरुपति में २२-२४ फरवरी २०१६ को हुए तीन दिवसीय अन्तराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन यूजीसी सेंटर फॉर साउथईस्ट एशियन एंड पैसेफिक स्टडीज, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, तिरुपति, आध्र प्रदेश में हुआ। इस सेमीनार में भारत, वियतनाम, जापान, अफगानिस्तान, ईरान और श्रीलंका से आये शोधार्थियों ने भाग लिया. आई.सी.डब्ल्यू.ए. की तरफ से डॉ ध्रुबज्योति भट्टाचार्य ने भाग लिया तथा एक शोध पत्र भी प्रस्तुतं किया।

दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार- "इंडियाज नार्थईस्ट स्टेटस एंड ईस्टर्न नेबर्स" द वे फॉरवर्ड", शिलोंग, मेघालय, आई.सी.डब्ल्यू.ए. के सौजन्य से, ५-६ दिसम्बर २०१५

एशियन कांफ्लुएंस यंग स्कोलर फोरम द्वारा ५-६ दिसम्बर २०१५ को शिलोंग में दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में सम्पूर्ण क्षेत्र के प्रख्यात विद्वान एवं शोधार्थियों भाग लिया। सेमिनार में एक्ट ईस्ट नीति की सफलता के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों की महत्वपूर्ण एकीकृत भूमिका पर चर्चा हुई। आई.सी.डब्ल्यू.ए. की तरफ से डॉ स्तुति बनर्जी ने भाग लिया तथा एक शोध पत्र भी प्रस्तुतं किया

विश्व मामलों की भारतीय परिषद् के बारे में

विश्व मामलों की भारतीय परिषद एक थिंक टैंक के रूप में भारतीय बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा १९४३ में स्थापित किया गया था। यह सोसायटी अधिनियम १८६० के पंजीकरण के अंतर्गत एक गैर सरकारी, गैर राजनीतिक और गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया था। २००१ में संसद के एक अधिनियम द्वारा, विश्व मामलों की भारतीय परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति आईसीडब्ल्यूए के पदेन अध्यक्ष हैं। परिषद् शोध संकाय के आंतरिक वैचारिक मंथन और बाहरी बुद्धिजीवियों के सहयोग से नीतिगत शोध निर्मित करती है। परिषद् नियमित रूप से सेमिनार, गोलमेज सम्मेलन, व्याख्यान, परिचर्चा आदि का आयोजन करवाती है। यहाँ एक प्रतिष्ठित पुस्तकालय है, और इंडिया क्वाटर्ली जैसे जरनल/मैगजीन का प्रकाशन होता है। इसका एक अपना अलग वेब साइट है। यह परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर भारत की भूमिका को प्रदर्शित करती है और अन्य विदेशी थिंक टैंकों के साथ संवाद स्थापित कर ट्रैक टू के लिए मंच तैयार करती है।

आई सी डब्ल्यू ए द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रक, सप्रू हाउस, बाराखम्बा रोड़, न ई दि ल्ली – ११०००१
वेबसाईट: http://www.icwa.in; दूरभाष नं. 011-23317246 फैक्स नं. 011-23310638

दिशा निर्देशक
राजदूत नलिन सूरी, महानिदेशक, विमाभाप, सप्रू हाउस, नई दिल्ली.

संपादक
श्री पियूष श्रीवास्तव, भारतीय विदेश सेवा, संयुक्त सचिव, आई.सी.डब्ल्यू.ए., सप्रू हाउस, नई दिल्ली.

प्रबंधकीय संपादक
डॉ पंकज कुमार झा, शोध निदेशक, आई.सी.डब्ल्यू.ए.

सहायक संपादक
डॉ राकेश कुमार मीना, शोध अध्येता, आई.सी.डब्ल्यू.ए.